एनआईसी तेलंगाना: तेलंगाना की डिजिटल कैबिनेट पहल: ई-कैबिनेट प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित पेपरलेस और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

डिजिटल कैबिनेट के साथ तेलंगाना ने कागज रहित शासन अपनाया

डिजिटल गवर्नेंस की अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में, **तेलंगाना सरकार** ने **2 जुलाई 2026** को **एनआईसी ई-कैबिनेट प्रणाली को डिजिटल कैबिनेट के रूप में** सफलतापूर्वक लागू किया है, जो पारंपरिक कागज-आधारित कैबिनेट बैठकों से एक सुरक्षित, पूरी तरह से डिजिटल निर्णय लेने के मंच में एक परिवर्तनकारी बदलाव है, जिसे **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), उत्तराखंड द्वारा विकसित** और **एनआईसी तेलंगाना, आईटीई एंड सी और जीएडी (कैबिनेट) विभाग, तेलंगाना के सामूहिक समन्वय और तकनीकी समर्थन और अनुकूलित किया गया है।** यह पहल कुशल, पारदर्शी और पर्यावरण की दृष्टि से सतत शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी द्वारा 2 जुलाई 2026 को तेलंगाना सचिवालय में पहली डिजिटल कैबिनेट पहल बैठक का शुभारंभ।

8 जून 2026 को, श्री अनुदीप दुरिशेट्टी, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव (आई.टी.), आई.टी.ई. एंड सी और श्री गुंटुकु प्रसाद, एस.आई.ओ. और डी.डी.जी. तेलंगाना के बीच कार्यान्वयन हस्ताक्षर औपचारिक रूप से पूरा हुआ।

समूह फोटो: श्री गुंटुकु प्रसाद, एसआईओ तेलंगाना और डीडीजी, श्री अरुण शर्मा, वैज्ञानिक-ई, ईकैबिनेट प्रोजेक्ट एचओडी, एनआईसी उत्तराखंड, श्री रायनील जॉन, वैज्ञानिक- एफ और एचओडी और एएसआईओ (डिस्ट्.), श्री श्रीनिवास राव, वैज्ञानिक-ई, श्री वीवीएसएन प्रसाद, वैज्ञानिक-ई, सुश्री बी.सीता महालक्ष्मी, वैज्ञानिक-सी, एनआईसी तेलंगाना, तब मुख्य सचिव श्री रामकृष्ण राव और श्री अनुदीप दुरिशेट्टी, आईएएस, संयुक्त सचिव (आईटी), आईटीई एंड सी और श्री रघुनंदन राव, आईएएस, तेलंगाना और आईटीई एंड सी और जीएडी टीम के अधिकारियों के साथ।

डिजिटल कैबिनेट (ई-कैबिनेट प्लेटफॉर्म) पहल के मुख्य अंश:

डिजिटल कैबिनेट प्रणाली ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को कैबिनेट एजेंडा नोट्स, सहायक दस्तावेजों, नीति प्रस्तावों और निर्णयों तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंचने में सक्षम बनाया, जो कि आईपैड उपकरणों पर स्थापित और कॉन्फ़िगर किए गए डिजिटल कैबिनेट मोबाइल ऐप के माध्यम से और परिचय द्वारा प्रमाणित थे, जिससे मुद्रित फ़ाइलों की आवश्यकता समाप्त हो गई।

इस प्रणाली ने एजेंडा तैयार करने और मीटिंग नोटिस दस्तावेज़ों के प्रसार और एनआईसी एसएमएस और ईमेल सेवाओं के माध्यम से सूचनाओं/अलर्ट, संबंधित विभागों के सचिवों के लिए वेटिंग लाउंज टीवी हॉल में चल रहे और पूरे हो चुके एजेंडा मदों की प्रगति से लेकर निर्णय रिकॉर्डिंग और अभिलेखीय और मीटिंग प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल के माध्यम से बैठक के समापन तक, कैबिनेट के पूरे कार्यप्रवाह (बैठक से पहले और बैठक के दौरान की प्रक्रिया) को डिजिटाइज़ किया।

डिजिटल कैबिनेट (ई-कैबिनेट प्लेटफॉर्म) की पहल के लाभ

- त्वरित निर्णय-प्रक्रिया
- बेहतर प्रशासनिक दक्षता
- मंत्रिमंडल की कार्यवाही की सुरक्षा और गोपनीयता में वृद्धि
- बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही
- पर्यावरण के अनुकूल शासन पद्धतियाँ

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) की भूमिका

इस पहल की शुरुआत तत्कालीन **मुख्य सचिव श्री रामकृष्ण राव** और **श्री अनुदीप दुरिशेट्टी, आईएएस, संयुक्त सचिव (आईटी), आईटीई एंड सी और श्री रघुनंदन राव, आईएएस, तेलंगाना** द्वारा **जून 2026** के पहले सप्ताह में की गई थी।

एनआईसी ने ई-कैबिनेट प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें **श्री गुंटुकु प्रसाद, एसआईओ तेलंगाना और डीडीजी, श्री अरुण शर्मा, वैज्ञानिक-ई, ईकैबिनेट परियोजना एचओडी, एनआईसी उत्तराखंड; श्री रेनिल जॉन, वैज्ञानिक- एफ और एचओडी, श्री श्रीनिवास राव, वैज्ञानिक-ई, श्री वीवीएसएन प्रसाद, वैज्ञानिक-ई, सुश्री बी.सीता महालक्ष्मी, वैज्ञानिक-सी, एनआईसी तेलंगाना, के साथ कार्यान्वयन रणनीति, पूर्व-आवश्यकताओं, अंतर विश्लेषण, उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग, बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, प्रशिक्षण और तेलंगाना में डिजिटल कैबिनेट के रोलआउट के लिए गो-लाइव मील के पत्थर पर तकनीकी विशेषज्ञता और निरंतर समर्थन प्रदान करने के लिए आईटीई एंड सी, जीएडी टीम, तेलंगाना** के साथ विस्तृत चर्चा की गई।

एनआईसी उत्तराखंड के वैज्ञानिक-ई श्री अरुण शर्मा ने ई-कैबिनेट पोर्टल का प्रदर्शन **तेलंगाना के तब मुख्य सचिव श्री के. रामकृष्ण राव** को किया। इस प्रदर्शन में **श्री एम रघुनंदन राव, आईएएस, श्री गुंटुकु प्रसाद, एसआईओ और डीडीजी, श्री रेनिल जॉन, वैज्ञानिक-एफ और एचओडी, श्री एस. श्रीनिवास राव, वैज्ञानिक-ई और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया**, जिन्होंने सत्र में भाग लिया और डिजिटल कैबिनेट प्रणाली के कार्यान्वयन पहलुओं पर चर्चा की।

18 जून 2026 को, तेलंगाना के माननीय आईटी मंत्री श्री दुडिला श्रीधर बाबू ने **तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी** को ई-कैबिनेट पहल **"डिजिटल कैबिनेट"** के कार्यान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद के साथ **टैबलेट** सौंपे।

24 जून 2026 को श्री अनुदीप दुरिशेट्टी, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव (आई.टी.), आई.टी.ई. एंड सी और टीम के साथ **एन.आई.सी. उत्तराखंड और तेलंगाना टीम की उपस्थिति में डिजिटल कैबिनेट का एक मॉक रन** आयोजित किया गया।

आभार:

2 जुलाई 2026 को पहले डिजिटल कैबिनेट के सफल रोलआउट को पूरा करने पर, **संयुक्त सचिव (आईटी), आईटीई एंड सी, श्री अनुदीप दुरिशेट्टी आईएएस ने एनआईसी उत्तराखंड और तेलंगाना टीम, आईटीई एंड सी और जीएडी टीम द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य सॉफ्टवेयर समर्थन और टीम के प्रयासों की सराहना की।**

श्री गुंटुकु प्रसाद, एसआईओ और डीडीजी तेलंगाना ने भी श्री अरुण शर्मा, एनआईसी उत्तराखंड और टीम, श्री रेनिल जॉन, वैज्ञानिक- एफ और एचओडी, श्री श्रीनिवास राव, वैज्ञानिक-ई, श्री वीवीएसएन प्रसाद, वैज्ञानिक-ई, सुश्री बी. सीता महालक्ष्मी, वैज्ञानिक-सी, एनआईसी तेलंगाना द्वारा किए गए प्रयासों और कम समय में त्वरित रोल-आउट की सराहना की।

उन्होंने **श्री वी टी वी रमना, डीडीजी और राज्य समन्वयक, तेलंगाना को आवश्यक मार्गदर्शन और अनुमोदन के लिए विशेष धन्यवाद दिया** और साथ ही **उन्होंने इस पहल के लिए अपनी टीम को प्रतिनियुक्त** करने के लिए **एसआईओ उत्तराखंड** के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

निष्कर्ष:

श्री गुंटुकु प्रसाद, एसआईओ और डीडीजी तेलंगाना के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और अटूट समर्थन के तहत और **तेलंगाना सरकार** द्वारा **डिजिटल कैबिनेट पहल** के सफल कार्यान्वयन ने तेलंगाना के डिजिटल शासन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और इस असाइनमेंट के सफल निष्पादन को चिह्नित किया।

डिजिटल कैबिनेट की पहल की कुछ झलकियाँ:

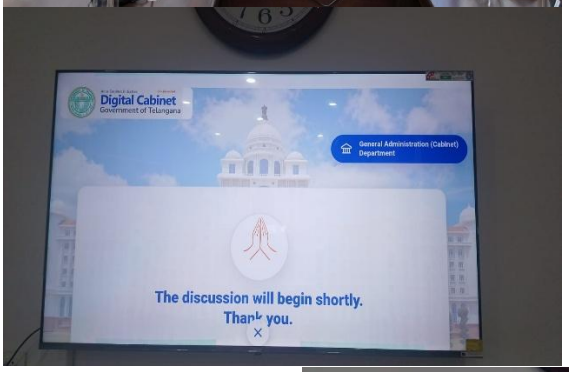

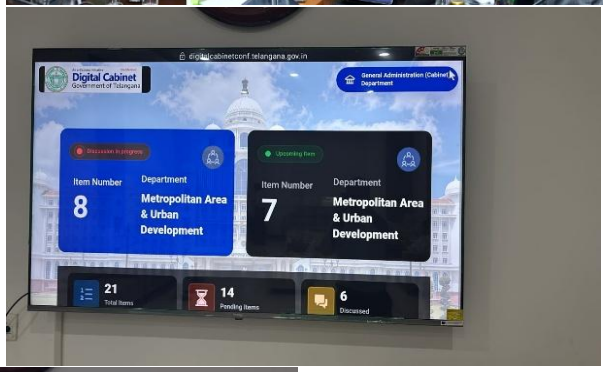

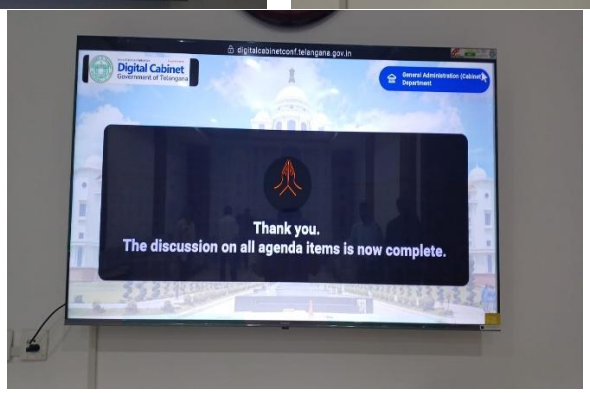

****